दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, गुरुवार 09 सितंबर 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 340

महत्वपूर्ण एवं खास

इंडोनेशियाई जेल में लगी आग, 41 कैदी जिंदा जले, 80 अस्पताल में भर्ती

जकार्ता । इंडोनेशिया की राजधानी के पास क्षमता से अधिक भरी एक जेल में बुधवार तड़के आग लग गई, जिसमें कम से कम 41 कैदियों की मौत हो गई जबकि 80 अन्य घायल हो गए। जकार्ता पुलिस प्रमुख फादिल इमरान ने घटनास्थल पर मौजूद संवाददाताओं को बताया कि आग पर करीब दो घंटे के भीतर काबू पा लिया गया और सैकड़ों पुलिसकर्मियों एवं सैनिकों को जेल के आस-पास तैनात किया गया है ताकि कैदियों को फरार होने से रोका जा सके। टेलीविजन पर प्रसारित फुटेज में दमकलकर्मी आग पर काबू पाने में संघर्ष करते और परिसर से काला धुआं उठते दिख रहा था। जकार्ता की बाहरी सीमा पर स्थित तांगेरंग जेल के एक कमरे में कई शव नारंगी रंग के थैलों में डालकर रखे गए। इमरान ने कहा, स्थिति अब नियंत्रण में है। साथ ही कहा कि कम से कम 41 कैदियों की मौत हुई है और 80 कैदियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जिनमें से आठ गंभीर रूप से झुलस गए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी आग के कारणों की अब भी जांच कर रहे हैं लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ब्लॉक के एक प्रकोष्ठ में शार्ट सर्किट के कारण आग लगी। न्याय मंत्रालय में सुधार विभाग की प्रवक्ता रीका अप्रिआंती ने बताया कि इसमें 1,225 कैदियों को रखने की जगह है लेकिन 2,000 से ज्यादा कैदी यहां बंद हैं।

फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश, आरोपी हुआ गिरफ्तार

भोपाल (आरएनएस)। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से एक अस्पताल में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने का मामला सामने आया है। ये फर्जी कार्ड बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि इस गिरोह के एक सदस्य कृष्णा कुशवाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकियों की तलाश अभी जारी है। यह मामला ग्वालियर शहर के कंपू थाना क्षेत्र का है। जहां ज्यारोग्य अस्पताल में पुलिस ने फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले गिरोह के एक सदस्य को पकड़ा है। जानकारी मिली है कि गिरोह का सदस्य कृष्णा कुशवाह ने अस्पताल में भर्ती मरीज राजकुमार का नकली आयुष्मान कार्ड बनाया था। वहीं आरोपी ने यह कार्ड 5 हजार रुपए लेकर बनाया था। दरअसल इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब, मरीज का लिस्ट में नाम नहीं आया। जिसके बाद पुलिस से इसकी शिकायत की गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी के पास से पुलिस ने एक लैपटॉप, एक थंब मशीन और 34 नकली आयुष्मान कार्ड बरामद किया है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का निधन

पटना (आरएनएस)। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का आज सुबह निधन हो गया। वह करीब 84 वर्ष के थे। स्व. सिंह के पुत्र शुभानंद मुकेश ने बुधवार को बताया कि उनके पिता लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तबियत अधिक बिगड़ने पर इलाज के लिए उन्हें राजधानी पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज सुबह उनका निधन हो गया। उल्लेखनीय है कि श्री सिंह का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा। वह भागलपुर जिले के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से लगातार नौ बार विधायक रह चुके है। वह पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा की सरकार में सिंचाई मंत्री भी रहे थे।

सड़क हादसे में बोलेरो सवार महिला समेत दो लोगों की मृत्यु

रायबरेली (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले के गुरुबख्शगंज इलाके में हुई सड़क दुर्घटना में बोलेरो सवार मिली समेत दो लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि दो लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीती देर शाम गुरुबख्शगंज इलाके में देदौर के पास तेज़ रफ़्तार बोलेरो वाहन सड़क पर खड़े ट्रैक्टर से टकरा गया। हादसे में प्रतापगढ़ निवासी 70 वर्षीय नकछेद सिंह और अरुण सिंह की पत्नी 48 वर्षीय बीना की मौके पर ही मृत्यु हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है।

कोरोना से हुई मौतों को इलाज में लापरवाही मानना सही नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मुआवजे की याचिका

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोरोना की वजह से होने वाली सभी मौतों के लिए चिकित्सकीय उपेक्षा की वजह से हुई। ऐसा कहते हुए कोर्ट ने उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें महामारी के मुश्किल वक्त में ऑक्सीजन की कमी और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई थी।

याचिका दीपक राज सिंह की ओर लगाई गई गई थी। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने याचिकाकर्ता से अपने सुझावों के साथ सक्षम अधिकारियों के पास जाने और

अपनी बात रखने के लिए कहा। कोर्ट ने पाया कि कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को प्रभावित किया और ऐसे में इलाज में लापरवाही जैसे आम अनुमान का लगाया जाना ठीक नहीं होगा। पीठ के मुताबिक, जैसाकि याचिका में कहा गया है कि कोरोना की वजह से हुई सभी मौतें इलाज में लापरवाही की वजह से हुई, ऐसा अनुमान कोर्ट नहीं लगा सकता। कोर्ट ने कोरोना महामारी से जुड़े उन मामलों का भी हवाला दिया, जिस पर स्वतः संज्ञान लिया गया है। कोर्ट ने कहा कि महामारी से जुड़े सभी पक्षों को देखने के लिए ही नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है। पीठ ने यह भी कहा कि शीर्ष कोर्ट ने कोरोना से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के लिए 30 जून को आदेश भी जारी किया था। अपने 30 जून के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का एक वैधानिक दायित्व है कि वह कोरोना महामारी के पीड़ितों के लिए न्यूनतम अनुग्रह सहायता की सिफारिश करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करे। इसके बाद याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि उस फैसले में अदालत ने मानवता के संबंध में विचार किया है न कि लापरवाही के कारण। सरकार अभी तक नीति के साथ सामने नहीं आई है। यदि आपके पास उस नीति के कार्यान्वयन के संबंध में कोई सुझाव है, तो आप सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

ईडी निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय सहीः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक एसके मिश्रा के कार्यकाल को बढाने के केंद्र सरकार के निर्णय को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा कि केंद्र के पास यह शक्ति है लेकिन इसे केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने हालांकि यह स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति की आयु में पहुंच चुके अधिकारियों के कार्यकाल में विस्तार दुर्लभ और अपवाद वाले मामलों में किया जाना चाहिए। एनजीओ 'कॉमन कॉज' ने ईडी के निदेशक के तौर पर मिश्रा के, 2018 के नियुक्ति आदेश में पूर्व प्रभावी बदलाव को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी जिस पर यह फैसला आया है।

क्यूबा में दो साल के बच्चों को लगाई गई पहली वैक्सीन

हवाना। क्यूबा में दो साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही क्यूबा ऐसा पहला देश बन गया है, जहां पर इतने कम उम्र के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। जो वैक्सीन बच्चों को लगाई जा रही है वह क्यूबा में ही तैयार की गई है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से इन वैक्सीन को मान्यता नहीं दी गई है। क्यूबा में अब्दला और सोबराना नाम की कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। बच्चों पर इनका क्लीनिकल ट्रायल पूरा हो गया है।

शुक्रवार को क्यूबा में बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई। क्यूबा की रेग्युलेटरी अथॉरिटी की निदेशक ओल्गा लीडिया जैकोबो ने बतायी कि यह बहुत कठिन प्रक्रिया रही, जहां पर बच्चों पर क्लीनाकल ट्रायल का मूल्यांकन किया गया। फिलहाल क्यूबा के सिएनफ्यूगोस शहर में ही इस आयुवर्ग के बच्चों को वैक्सीन लगी है।

क्यूबा में 3 सितम्बर को 12 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी। इसके बाद सोमवार से देश में 2 से 11 साल के बच्चों को वैक्सीन लगानी शुरू की गई। चीन, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला जैसे देशों ने भी छोटे बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की घोषणा की है लेकिन अभी इसकी शुरुआत नहीं की गई है। भारत में भी 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी हो रही है। इसके तहत जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को देश में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा चिली ने भी 6 से 12 साल के बच्चों के लिए चीनी वैक्सीन सिनोवैक को हरी झंडी दिखा दी है।

उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिया इस्तीफा

देहरादून (आरएनएस)। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मौर्य दो दिन पहले नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलीं थीं। उनके इस्तीफे के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ओर से कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर वह आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से मैदान में उतर सकती हैं। राज्यपाल के सचिव बृजेश कुमार संत ने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को भेज दिया है, जो अभी स्वीकार नहीं हुआ है। 1956 में जन्मीं बेबी रानी मौर्य अगस्त 2018

में कृष्ण कांत पॉल की जगह उत्तराखंड की राज्यपाल बनी थीं। यहां की राज्यपाल बनने से पहले वह 1995 से वर्ष 2000 तक आगरा की मेयर भी रही चुकी हैं। मौर्य उत्तराखंड की दूसरी महिला गवर्नर थीं। इससे पहले, मार्गरेट अल्वा अगस्त 2009 से मई 2012 तक उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। मौर्य के इस्तीफे के साथ अब उत्तराखंड का अगला राज्यपाल कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इससे पहले बीजेपी ने आज उत्तर प्रदेश समेत 5 चुनावी राज्यों के लिए चुनाव प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया है।

महिलाओं को एनडीए के जरिए सशस्त्र बलों में मिलेगी एंट्री

» केंद्र सरकार ने भेदभाव खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहा

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सशस्त्र बल देश में एक बहुत ही सम्मानजनक बल हैं, लेकिन उन्हें बलों में लैंगिक समानता की दिशा में और अधिक करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसे उम्मीद है कि रक्षा बल उस महत्वपूर्ण भूमिका को महत्व देंगे जो महिलाएं निभा रही हैं।

इसपर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में लड़कियों को शामिल करने की अनुमति देने का फैसला कल लिया गया है। केंद्र का कहना है कि तीन सेना प्रमुखों से सलाह मशविरा करने के बाद यह फैसला लिया गया है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह जानकर बेहद खुशी हुई कि सशस्त्र बलों ने खुद महिलाओं को एनडीए में शामिल करने का निर्णय लिया है। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को बताया कि केंद्र ने तीन सेवा प्रमुखों के साथ विचार-विमर्श के बाद कल यह फैसला किया। एएसजी भाटी ने कहा कि यह एक अच्छी खबर है। बलों और सरकार के उच्चतम स्तर पर निर्णय लिया गया है कि महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के माध्यम से स्थायी कमीशन के लिए शामिल किया जाएगा। यह निर्णय कल देर शाम लिया गया। पीठ ने कहा कि वह चाहती है कि रक्षा बल लैंगिक समानता के प्रति अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाएं, बजाय इसके कि अदालत उन्हें ऐसा करने का निर्देश दे। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि हम समय-समय पर अधिकारियों को खुद ऐसा करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। हमें विश्वास है कि वे नियम विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। यह हमारे लिए खुशी की स्थिति नहीं है।

वायु सेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन आज

» बाड़मेर में राजमार्ग की हवाई पट्टी तैयार

नईदिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एमरजेंसी लैंडिंग फील्ड (ईएलएफ) का आज उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे राजस्थान के बाड़मेर के दक्षिण में गांधव-बाखासर सेक्शन (राष्ट्रीय राजमार्ग-925) पर एमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर वैमानिक गतिविधियों का अवलोकन करेंगे। यह पहली बार है जब किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग भारतीय वायुसेना के विमानों की एमरजेंसी लैंडिंग के लिये किया जायेगा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्ग-925ए पर सत्ता-गांधव के 41/430 किमी से 44/430 किमी के तीन किलोमीटर लंबे हिस्से को भारतीय वायु सेना के लिये एमरजेंसी लैंडिंग फील्ड (ईएलएफ) के रूप में तैयार किया है। लैंडिंग सुविधा, अभी हाल में विकसित खंड़जे से बने ऊंचे किनारे वाले (फुटपाथ के रूप में) दो लेन के गगरिया-भाखासर तथा सत्ता-गांधव सेक्शन का हिस्सा है। इसकी कुल लंबाई 196.97 किमी है और इसकी लागत 765.52 करोड़ रुपये है। इसे भारतमाला परियोजना के तहत निर्मित किया गया है। इस परियोजना से बाड़मेर और जालौर जिले के सीमावर्ती गांवों के बीच संपर्कता में सुधार होगा। यह हिस्सा पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है और इससे भारतीय सेना की सतर्कता बढ़ेगी और देश की अधोसंरचना भी मजबूत

होगी।

इस एमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप के अलावा वायुसेना/भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुये कुंदनपुरा, सिंघानिया और भाखासर गांवों में 100ङ्क30 मीटर आकार के तीन हेलीपैड भी बनाये गये हैं। इस निर्माण से भारतीय सेना तथा देश की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी।

ईएलएफ का निर्माण 19 महीनों के भीतर कर लिया गया था। ईएलएफ के लिये निर्माण कार्य की शुरूआत जुलाई 2019 में हुई थी और उसे जनवरी 2921 में पूरा कर लिया गया। भारतीय वायुसेना और एनएचएआई की देखरेख में यह निर्माण कार्य मेसर्स जीएचवी इंडिया प्रा.लि. ने किया था। सामान्य दिनों में ईएलएफ का इस्तेमाल निर्बाध यातायात के लिये किया जायेगा, लेकिन जब वायुसेना को अपनी गतिविधियों के लिये इस ईएलएफ की जरूरत होगी, तो सर्विस रोड को यातायात के लिये इस्तेमाल किया जायेगा। सर्विस रोड से भी आराम से यातायात चल सकता है। ईएलएफ की लंबाई 3.5 किलोमीटर है। इस लैंडिंग स्ट्रिप पर भारतीय वायुसेना के हर प्रकार के विमान उतर सकेंगे।

काबुल में अखबार के लिए काम करने वाले 5 पत्रकारों को किया गिरफ्तार

» सरकार बनते ही तालिबान की तानाशाही शुरू

काबुल । तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होते ही पत्रकारों पर जुल्म करना शुरू कर दिया है. स्थानीय चैनल टोलो न्यूज के अनुसार, काबुल के दैनिक अखबार एतिलातरोज के लिए काम करने वाले पांच पत्रकारों को बुधवार को गिरफ्तार किया गया है. ये गिरफ्तारी तालिबान ने की है. हालांकि अभी मामले में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है कि इस कार्रवाई के पीछे की असल वजह क्या है. हालांकि तालिबान लगातार मीडिया संगठनों के प्रति सख्ती दिखा रहा है.

तालिबान ने साफ तौर पर कहा है कि अफगान मीडिया पहले की तरह काम कर सकता है लेकिन साथ ही मीडिया को कुछ चेतावनी भी दी है. तालिबानी प्रवक्ता ने कहा है कि मीडिया को आलोचना करने की अनुमति है लेकिन वह किसी का चरित्र हनन नहीं कर सकता. दुनिया के सामने खुद को बदला हुआ दिखाने और महिलाओं के प्रति नरम रुख का नाटक करते हुए तालिबान के एक नेता ने हाल ही में महिला पत्रकार को इंटरव्यू भी दिया था. लेकिन कई अफगान और मीडिया संगठन तालिबान पर विश्वास करने को तैयार नहीं हैं.

गणपति महोत्सव पर रेलवे चलाएगा 261 स्पेशल ट्रेन, स्पेशल किराया संग पूरी तरह होंगी आरक्षित

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय रेल की गणपति स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है। इस महोत्सव में होने वाली भीड़ से बचने के लिए रेलवे 261 स्पेशल ट्रेने चला रही है। मिली जानकारी के अनुसार 201 स्पेशल ट्रेनें सेंट्रल रेलवे, 42 पश्चिम रेलवे और कोंकण रेल कॉरपोरेशन से 18 ट्रेन चल रही हैं।

रेल मंत्रालय के मुताबिक ये गणपति स्पेशल ट्रेन 20 सितंबर तक चलाई जाएंगी। पूरे देश में अलग-अलग जगह से चलने वाली ट्रेनों का किराया भी स्पेशल होगा। रेलवे के मुताबिक, ये ट्रेनें पूरी तरह आरक्षित हैं। अधिकारियों का कहना है कि गणेश महोत्सव में काफी संख्या में लोग यात्रा

करते हैं, जिससे यात्रियों की संख्या में एकाएक इजाफा होता है। इससे बचने के लिए स्पेशल ट्रेने चल रही हैं। ये ट्रेने अगस्त के अंतिम सप्ताह से शुरू हो चुकी हैं। इसमें स्लीपर क्लास के अलावा अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं।

कई ट्रेनों का होगा यात्रा विस्तार

रेलवे के मुताबिक नई समय-सारणी में कई साप्ताहिक एक्सप्रेस को यात्रा विस्तार दिया जाएगा तो कई के रूट परिवर्तन और कई ट्रेन के स्टेशन में भी परिवर्तन होना है। इस कड़ी में उत्तर रेलवे ने ट्रेन संख्या 20503/02504 नई दिल्ली-डिब्रूगढ़-नई दिल्ली साप्ताहिक राजधानी ट्रेन को सप्ताह में पांच दिन चलाने निर्णय लिया है। इसी तरह ट्रेन संख्या 54769/54770 तिलक ब्रिज-रोहतक-तिलक ब्रिज पैसेंजर को भिवानी तक ही चलेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 54423/54424 दिल्ली-जंक्शन-भिवानी-दिल्ली जंक्शन को हिसार तक ही चलाने का निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा ट्रेन संख्या 04051/ 04052 नई दिल्ली-दोराई-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल का टर्मिनल बदला गया है। ट्रेन संख्या 04051 नई दिल्ली-दोराई शताब्दी स्पेशल अजमेर से संचालित होगी। एक अन्य निर्णय में रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रख ट्रेन संख्या 09009/09010 मुंबई सेंट्रल-नई दिल्ली-मुम्बई सेंट्रल द्वि-साप्ताहिक दूरंतो सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन को आगामी सूचना तक तत्काल प्रभाव से बहाल करने का निर्णय लिया है। आमूमन रेलवे की समय-सारणी जुलाई में लागू होती है। लेकिन कोविड की वजह से इस साल नई समय-सारणी अक्तूबर से लागू होगी।

5जी नेटवर्क पर क्लाउड गेमिंग का मिलेगा अनुभव - मोबाइल पर ऑनलाइन वीडियो गेम का अब अलग अनुभव मिलेगा। किसी भी वीडियो गेम को बिना डाउनलोड किए खेला जा सकेगा। इतना ही नहीं रियल टाइम गेमिंग भी संभव होगा। खासाबात यह है कि दिल्ली मेट्रो, बस, एनसीआर में चलने वाली ट्रेन में बैठक कर भी यात्री रियल टाइम वीडियो गेम खेल कर मन बहला सकेंगे। स्मार्टफोन पर क्लाउड गेमिंग की भी शुरुआत हो गई है। दरअसल क्लाउड गेमिंग एयरटेल के 5जी नेटवर्क पर मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा आवंटित स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया जा रहा है। मोबाईल पर हाई एंड कंप्यूटर स्ट्रीम किया जा सकेगा। यानी वीडियो गेम खेलने के लिए उसे डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी।